

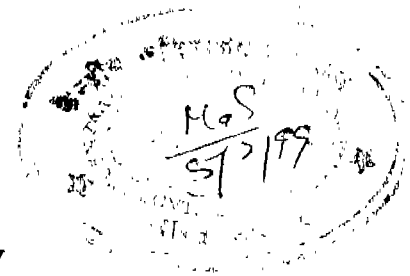


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I  
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 206]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 1998/भाद्र 24, 1920

No. 206]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 1998/BHADRA 24, 1920

खाणिज्य मंत्रालय

(सार्वजनिक सूचना संख्या 40 (आर. ई.-98)/1997-2002)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1998

फा. सं. पी. आर. यू./ए. एस./98-99/स्पेशल पैकेज.—सांविधिक आदेश संख्या 283 (अ) दिनांक 31-3-97 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड-2 में यथा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 के पैराग्राफ 4.11 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (आर. ई. 98), 1997-2002 में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. पैराग्राफ 7.38 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

उन मामलों में जहां निर्यात प्राप्तियों की वसूली के बाद डी ई पी बी क्रेडिट मंजूर करने के लिए आवेदन किया जाता है, मुक्त विदेशी मुद्रा में पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को प्राधिकृत डीलरों टी/टी खरीदारी/मांग खरीदारी दर पर, जैसा मामला हो, दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख को प्रचलित भारतीय रुपयों में परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रकार परिकल्पित पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर क्रेडिट की डी ई पी बी दर लागू होगी।

2. पैराग्राफ 7.39 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

तथापि, उन मामलों में जहां निर्यात प्राप्तियों की वसूली के बाद क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाता है, की वसूली की अंतिम तारीख से परिकल्पित वसूली की तारीख से 90 दिनों के भीतर यह आवेदन किया जा सकता है, जिनके लिए दावा फाइल किया गया है।

3. पैराग्राफ 7.7 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

उन आवेदनों के संबंध में जिनके लिए मानक निवेश उत्पादन मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं, उस शर्त के मद्दे आवेदक द्वारा आवेदन किया जाएगा कि आवेदन की प्राप्ति से छः महीनों के भीतर विशेष अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा निवेश उत्पादन मानदण्डों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जहां कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं अग्रिम लाइसेंस को जारी करने हेतु वित्तीय शक्तियों के अनुसार क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा नीति के पैराग्राफ 7.4 के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। आवेदक यह वचन देगा कि वह विशेष अग्रिम लाइसेंसिंग समिति (एस ए एल सी) द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन करेगा और तदनुसार एस ए एल सी द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपयोग न की गई निविष्टि पर 24% ब्याज के साथ शुल्क देना। वह प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) (संशोधित संस्करण-98)/1997-2002 के पैराग्राफ 7.28क (2) (ख) के अनुसार विशेष आयात लाइसेंस भी लौटाएगा। ऐसे मामलों में जहाँ, एस ए एल सी द्वारा 6 माह के भीतर मानदण्डों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है वहाँ यथा लागू मानदण्डों को अंतिम माना जाएगा, और कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

4. परिशिष्ट 11 ख में घोषणा/वचन के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

8. मैं/हम एल द्वारा करता हूँ/करते हैं कि ऐसे उत्पाद जिनके संबंध में मानक निवेश उत्पाद मानदण्ड निर्धारित नहीं किए जाते हैं, हम एस ए एल सी द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए गए मानदण्डों को मानने के लिए बाध्य होंगे और एस ए एल सी द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपयोग में न लाए गए निवेश पर 24% ब्याज के साथ सरकार को सीमा शुल्क का भुगतान करेंगे। हम प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) (संशोधित संस्करण-98) 1997-2002 के पैराग्राफ 7.28 क (2) (ख) के अनुसार विशेष आयात लाइसेंस को भी लौटा देंगे।

5. पैराग्राफ 7.5 में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

जहां मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड निर्धारित नहीं किए जाते हैं, लाइसेंसिंग प्राधिकारी आवेदक द्वारा स्वबोधना और वचनबद्धता के आधार पर नीति के पैरा 7.4 की शर्तों के अनुसार पात्र निर्यातकों को वास्तविक उपयोगकर्ता गैर-हस्तांतरियता की शर्तों के साथ अग्रिम लाइसेंस भी जारी कर सकता है बशर्ते कि पैराग्राफ 7.7 में यथाउल्लिखित एस ए एल सी द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अंतिम समायोजन किया जाए।

6. परिशिष्ट ख से ड तक यथाउल्लिखित सनदी लेखाकार के प्रथम पैराग्राफ में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :

(1) मैसर्स (आवेदक का पूरा नाम और पता) ने 1 अप्रैल, 1997 से निर्यात किया है जो अप्रैल-सितम्बर/अक्टूबर-मार्च (जो भी लागू हो) के दौरान किया गया।

7. परिशिष्ट 44 के पैराग्राफ 4 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

“एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट विनिर्माण उत्पादन या प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं सहित सभी प्रकार की वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात कर सकता है बशर्ते ये आयात की निषेधात्मक सूची में निषिद्ध मर्दे न हों। केन्द्र सरकार, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के उपक्रमों या किसी भी संगठन द्वारा स्थापित और अन्तर-मंत्रालयीय स्थायी समिति और भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा विधिवत स्वीकृत सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर विकास, डाटा एंट्री और कंवरशन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा विश्लेषण और कम्प्लेक्स में नियंत्रण या डाटा प्रबन्धन यूनिट द्वारा इस्तेमाल के लिए केन्द्रीय सुविधा के सृजन के लिए सभी प्रकार की वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात कर सकता है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों को विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित अवधि के लिए ग्राहकों से ऋण पर वस्तुओं के आयात की भी अनुमति होगी।”

स्पष्टीकरण :

1. “अन्तर-मंत्रालयीय स्थायी समिति” का आशय भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 117 (अ) दिनांक 22-2-93 द्वारा गठित इलैक्ट्रॉनिक्स हाईवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई एच टी पी) और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी सी) में सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के लिए अन्तर-मंत्रालयीय स्थायी समिति है।

2. “भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स” का आशय इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित और समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 की संख्या 21) के अधीन पंजीकृत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया सोसायटी है।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE

[Public Notice No. 40 (Re-98)/1997-2002]

New Delhi, the 15th September, 1998

**F. No. PRU/AS/98-99/Special Package.**—In exercise of powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997-2002, as notified in the Gazette of India Extraordinary, Part-II Section 3 Sub-section (ii) vide S. O. No. 283 (E) dated 31-3-97, the Director General of Foreign Trade hereby makes following amendment in the Handbook of Procedures (Vol. I) (RE-98), 1997-2002 :

1. The following may be added at the end of paragraph 7.38 :

In cases where the application for grant of DEPB credit is filed after realisation of export proceeds, the FOB value in free foreign exchange shall be converted into Indian Rupees as per authorised dealers T/T buying/on demand buying rate, as the case may be, prevalent on the date of realisation of proceeds. The DEPB rate of credit shall be applied on the FOB value so arrived.

**2. The following may be added at the end of paragraph 7.39 :**

However, in cases where the application for obtaining credit is filed after realisation of export proceeds, such application may be filed within 90 days from the date of realisation reckoned from the last date of realisation in respect of shipments for which the claim has been filed.

**3. The following may be added at the end of paragraph 7.7 :**

In respect of applications for which Standard Input Output Norms are not fixed, Advance licence under paragraph 7.4 of the policy shall be issued by regional licensing authorities, as per the financial powers for issuance of Advance licence where norms are fixed, as applied for by the applicant subject to the condition that input output ratio shall be finalised by SALC within six months from the date of receipt of application. The applicant shall give an undertaking that he shall abide by the norms fixed by SALC and accordingly pay duty together with 24% interest on the utilised inputs as per norms fixed by SALC. He shall also surrender SIL as per paragraph 7.28 A (ii) (b) of Handbook of procedures (Vol. I) (RE-98) 1997-2002. In cases, where the norms are not finalised by SALC within six months, the norms as applied for shall be treated as final and no adjustment will be made.

**4. The following may be added at the end declaration/undertaking in appendix 11B.**

8. I/we hereby declare that in respect of product for which Standard Input Output Norms are not fixed, we shall abide by the final fixation of norms by SALC and shall pay to the Government customs duty together with 24% interest on the unutilised inputs as per norms fixed by SALC. We shall also surrender SIL as per paragraph 7.28A (ii) (b) of Handbook of Procedures (Vol. I) (RE-98) 1997—2002.

**5. The paragraph 7.5 may be amended to read as follows :**

The licensing Authority may also issue Advance licences with actual user non transferable condition to eligible exporters in terms of paragraph 7.4 of the Policy, where Standard Input Output Norms are not fixed, based on self declaration and undertaking by the applicant subject to final adjustment as per norms fixed by SALC as stipulated in paragraph 7.7.

**6. The first paragraph of Chartered Accountant as given in Appendix 20 B to E may be modified as follows :**

(i) M/s. (Full name and addresss of the applicant) have made the exports from 1-4-97 which was realised during April-September/October-March (whichever is applicable).

**7. Paragraph 4 of appendix 44 shall be amended to read as follows :**

"A Software Technology Park unit may import free of duty all types of goods, including capital goods required by it for manufacture, production or processing provided they are not prohibited items in the negative list of imports. The Software Technology Parks Complex set up by the Central Government, Public or Private Sector Undertakings or any combination, duly approved by the Inter-Ministerial Standing Committee and Software Technology Parks of India may also import free of duty all types of goods, for creating Central facility for use by the software development, data entry and conversion, data processing, data analysis and control or data management units in the Complex. Software Technology Park units shall also be permitted to import goods on loan from clients for specified periods for executing specified projects.

**Explanation :—**

1. "Inter-Ministerial Standing Committee" means Inter-Ministerial Standing Committee for Hundred Per Cent Export Oriented Units in the Electronics Hardware Technology Parks (EHTP) and Software Technology Parks (STP) appointed by the notification of the Government of India, in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development no. S.O. 117 (E) dated 22-2-93.

2. "Software Technology Parks of India" means Software Technology Parks of India Society established by the Deptt. of Electronics, Government of India and registered under Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860).

This issues in public interest.

N. L. LAKHANPAL,

Director General of Foreign Trade and

Ex. Officio Adl. Secy.

